



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ११, अंक ९]

मंगळवार, एप्रिल २२, २०२५/वैशाख २, शके १९४७

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १३

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांकित १५ अप्रैल २०२५।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. I OF 2025.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCIL,
NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १ सन् २०२५।

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर
संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान
सन् १९६५ हैं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और
का महा. ४०। औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक
हुआ है ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खंड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण। १. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०२५ कहलाए।

(१) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ३४१ख-५ का प्रतिस्थापन। २. महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ की धारा ३४१ख-५ के स्थान में निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

पार्षदों द्वारा नगर पंचायतों के अध्यक्ष को हटाना।

“३४१ख-५. (१) धारा ३४१ख-१ के अधीन निर्वाचित **नगर पंचायत** का अध्यक्ष यदि पार्षदों की कुल संख्या के दो-तिहाई से कम न हो, के बहुमत द्वारा विशेष बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा इस प्रकार विनिश्चय किया गया है तो अध्यक्ष होने से परिवर्तित होगा:

परन्तु, अध्यक्ष के निर्वाचन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसा कोई प्रस्ताव लाया नहीं जायेगा।

(२) ऐसी विशेष बैठक के मांगपत्र पर पार्षदों की कुल संख्या के आधे सदस्यों से कम न हो, के द्वारा हस्ताक्षर किये जाएँगे और उसे कलक्टर के पास भेजा जायेगा।

(३) कलक्टर उप-धारा (२) के अधीन मांग की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर **नगर पंचायत** की विशेष बैठक बुलाएगा :

परन्तु, जब कलक्टर विशेष बैठक बुलाता है तो, उसकी सूचना अध्यक्ष को देगा।

(४) उप-धारा (१) के अधीन प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठक की अध्यक्षता कलक्टर द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जायेगी, परन्तु, कलक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी को मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(५) नामनिर्देशित पार्षदों को अध्यक्ष को हटाने संबंधी किसी प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(६) यदि उप-धारा (३) के अधीन प्रयोजनों के लिए बुलाई गयी विशेष बैठक में अध्यक्ष को हटाने संबंधी किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं किया जाता है या, यथास्थिति, अस्विकृत किया जाता है तो अध्यक्ष को हटाने का कोई नया प्रस्ताव **नगर पंचायत** के समक्ष लाया नहीं जायेगा।”।

वक्तव्य

महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का महा. ४०) की धारा ३४१ख-१ के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक **नगर पंचायतों** जिनके आम निर्वाचन, महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०२२ (सन् २०२२ का महा. ४१) के प्रारम्भण के दिनांक के पूर्व लिए गए हैं तो प्रत्येक नगर पंचायतों का अध्यक्ष यह निर्वाचित पार्षदों द्वारा उनमें से निर्वाचित किया गया अध्यक्ष है।

२. उक्त अधिनियम की धारा ३४१ ख-५ के अधीन **नगर पंचायतों** के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया जिसमें पार्षदों की कुल संख्या के आधे से कम न हो, ने हस्ताक्षरित किए गये कलक्टर को भेजे जानेवाले जिसमें अध्यक्ष के विरुद्ध कदाचार के आरोप शामिल हैं मांगपत्र कलक्टर द्वारा जाँच करने, ऐसी जाँच के निष्कर्षों को सरकार को प्रस्तुत करने और कलक्टर द्वारा जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लेना सम्मिलित है।

यह उपबंध करना इष्टकर समझती है कि, निर्वाचित किये गए पार्षदों द्वारा अपने में से निर्वाचित अध्यक्ष यदि विशेष बैठक में पार्षदों की कुल संख्या के दो-तिहाई से कम न हो, के बहुमत से इस प्रकार विनिश्चित किये गये पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष परिवर्तित होगा। इसलिए, विशेष बैठक में पारित किये गए प्रस्ताव द्वारा पार्षदों द्वारा ऐसे अध्यक्ष को हटाने और उसकी प्रक्रिया के लिए उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा ३४१ख-५ के बजाय नवीन धारा प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित करती है।

३. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,
दिनांकित १५ अप्रैल २०२५।

सी. पी. राधाकृष्णन,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा मान से,—

डॉ. के. एच. गोविंद राज,
शासन के प्रधान सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।